

विचार बिन्दु

सौभाग्य वीर से डरता है और कायर को डराता है। –अज्ञात

लोकतंत्र की असली परीक्षा स्थानीय शासन में

लोकतंत्र में चुनाव केवल सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जिम्मेदारी सौंपने की प्रक्रिया है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल विकास, सुशासन और बेहतर नागरिक सुविधाओं के वादे करते हैं। मतदाता भी इन्हीं उम्मीदों के साथ अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधियों की असली परीक्षा शुरू होती है। यह परीक्षा भाषणों और राजनीतिक दावों से नहीं, बल्कि आम नागरिक के जीवन में आने वाले बदलावों से होती है। सड़कें बेहतर हुईं या नहीं, घरों तक स्वच्छ पानी पहुंचा या नहीं, सफाई व्यवस्था सुधरी या नहीं और नागरिकों की शिकायतों का समाधान समय पर हुआ या नहीं–लोकतंत्र की सफलता का वास्तविक आकलन इन्हीं सवालों से होना चाहिए।

राज्यायत चुनावों में इन दिनों चल रहे पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव इस विषय को और प्रासंगिक बनाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर 2०26 में जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के चुनावों के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम घोषित किया है। इस कार्यक्रम के तहत 41 जिला परिषदों, 457 पंचायत समितियों और 14,4०3 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जा रहे हैं। जयपुर जिले में चुनाव चार चरणों में निर्धारित किए गए हैं। यह चुनावी प्रक्रिया केवल प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर नहीं है, बल्कि ग्रामीण विकास की दिशा और स्थानीय लोकतंत्र की मजबूती पर विचार करने का भी अवसर है। इस व्यापक प्रक्रिया की जानकारी देता है।

पंचायत चुनावों की विशेषता यह है कि यहां मतदाता अपने प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से जानता है। गांव की सड़क, पेयजल, नाली, विद्यालय, स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक भूमि और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े सवाल सीधे पंचायत के कामकाज से जुड़ते हैं। सरपंच और वार्ड पंच की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे गांव के नागरिकों और प्रशासन के बीच सबसे नजदीकी कड़ी होते हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। उन्हें विभिन्न गांवों की जरूरतों, विकास योजनाओं और सरकारी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना होता है।

इसलिए पंचायत चुनावों में केवल जातीय समीकरण, व्यक्तिगत संबंध और राजनीतिक दलों की प्रतिय्धा ही चर्चा के विषय नहीं होने चाहिए। मतदाताओं को यह भी देखना चाहिए कि उम्मीदवार गांव की समस्याओं को कितना समझता है, सार्वजनिक धन के उपयोग में कितनी पारदर्शिता रख सकता है और विकास कार्यों को लेकर उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं। चुनाव के दौरान किए गए वादों का मूल्यांकन चुनाव के बाद भी होना चाहिए।

भारत में पंचायतीराज व्यवस्था को संवैधानिक मजबूती देने के लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया था। इसके माध्यम से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद जैसी संस्थाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान मिला। संविधान के भाग नौ में पंचायतों से संबंधित प्रावधान हैं, जबकि ग्यारहवीं अनुसूची में कृषि, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास तथा ग्रामी उन्मूलन सहित 29 विषयों का उल्लेख है, जिन्हें पंचायतों से जोड़ा जा सकता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को अपने विकास से जुड़े निर्णयों में भागीदारी का अवसर देना था।

हालांकि संवैधानिक प्रावधानों और जमीनी हकीकत के बीच अभी भी अंतर दिखाई देता है। पंचायतों को जिम्मेदारियां तो दी जाती हैं, लेकिन कई बार उनके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशिक्षित कर्मचारी या नियम लेने की स्वतंत्रता नहीं होती। विकास योजनाओं के लिए धन की उपलब्धता और उसका समय पर उपयोग भी महत्वपूर्ण है। यदि पंचायत को गांव की सड़क बनानी है, लेकिन स्वीकृति या बजट के लिए बार-बार दूसरे कार्यालयों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो विकास कार्यों में देरी हो सकती है। इसलिए पंचायतीराज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए केवल चुनाव कराना पर्याप्त नहीं है। पंचायतों को जिम्मेदारी के अनुरूप अधिकार, संसाधन और प्रशासनिक क्षमता भी देनी होगी।

ग्रामीण राजस्थान की चुनौतियां बहुआयामी हैं। कई गांवों में पेयजल की नियमित उपलब्धता, सिंचाई, ग्रामीण सड़कों का रखरखाव, नालियों की सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। किसानों के लिए कृषि उत्पादों का उचित मूल्य, पशुपालन, चारा, स्थानीय रोजगार और जल संरक्षण भी उतने ही आवश्यक हैं। युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना ग्रामीण विकास के महत्वपूर्ण आयाम हैं।

पंचायतों को इन समस्याओं का समाधान करने के लिए गांव की जरूरतों के अनुसार प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। विकास का अर्थ केवल नई इमारत बनाना या किसी सड़क का उद्घाटन करना नहीं है। असली विकास तब दिखाई देता है, जब सरकारी विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता सुधरे, स्वास्थ्य केंद्र में आवश्यक सेवाएं मिलें, पेयजल की समस्या कम हो और गांव के गरीब परिवारों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। सार्वजनिक धन का उपयोग ऐसी प्राम्थिकताओं पर होना चाहिए, जिनसे अधिकतम लोगों को वास्तविक लाभ मिले।

स्थानीय शासन की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण पैमाना पारदर्शिता भी है। ठामसभा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ठामसभा की नियमित बैठकें हों, विकास योजनाओं और बजट की जानकारी सार्वजनिक की जाए तथा मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किया जाए, तो अनियमितताओं की संभावना कम की जा सकती है। नागरिकों को यह जानने का अधिकार होना चाहिए कि गांव के विकास के लिए कितना धन मिला, कहाँ खर्च हुआ और कौन-से कार्य अभी अधूरे हैं।

इसके साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए। चुनाव जीतने के बाद प्रतिनिधि को गांव के लोगों से नियमित संवाद करना चाहिए। ग्रामसभा केवल औपचारिक बैठक न बने, बल्कि उसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, गरीब परिवारों और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। स्थानीय जरूरतों के बारे में निर्णय लेते समय उन युवाओं की आवाज भी सुनी जानी चाहिए, जिनकी समस्याएं अक्सर सार्वजनिक चर्चा में पीछे रह जाती हैं।

राजस्थान में पंचायत चुनावों का एक व्यापक आर्थिक महत्व भी है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो उसका असर कृषि, स्थानीय व्यापार, निर्माण और उपभोग पर पड़ेगा। यदि गांवों में सड़क, सिंचाई, भंडारण और बाजार तक पहुंच बेहतर होती है, तो किसानों की लागत घटाने और आय बढ़ाने की संभावनाएं मजबूत होती हैं। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने से शहरों की ओर मजबूरी में होने वाला पलायन भी कम किया जा सकता है। इस प्रकार पंचायतें केवल प्रशासनिक संस्थाएं नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने वाली इकाइयां भी हैं।

यहां एक और महत्वपूर्ण बात समझने की जरूरत है। पंचायत चुनावों में राजनीतिक दलों की भागीदारी और प्रतिस्पर्धा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है, लेकिन गांव का विकास किसी एक दल के हित से बड़ा विषय है। चुनाव के बाद निर्वाचित प्रतिनिधियों को राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। योग्य सरकार, जिला प्रशासन, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के बीच बेहतर समन्वय से ही विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव है।

लोकतंत्र में मतदाता की भूमिका भी मतदान के दिन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। नागरिकों को ग्रामसभा में भाग लेना, योजनाओं की जानकारी प्राप्त करना और सार्वजनिक कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखना चाहिए। यदि किसी काम में अनियमितता दिखाई देती है तो निर्धारित प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से शिकायत की जानी चाहिए। जागरूक नागरिक भागीदारी से ही स्थानीय संस्थाओं की जवाबदेही मजबूत होती है।

अंततः पंचायत चुनावों का महत्व केवल इस बात में नहीं है कि किस उम्मीदवार को कितने वोट मिले या किस राजनीतिक दल को कितनी सीटें मिलीं। असली महत्व इस बात का है कि अगले पांच वर्षों में गांवों के जीवन में क्या बदलाव आता है। क्या पेयजल की समस्या कम होती है? क्या ग्रामीण सड़कें बेहतर होती हैं? क्या विद्यालय और स्वास्थ्य केंद्र अधिक प्रभावी बनते हैं? क्या किसानों और युवाओं को नए अवसर मिलते हैं? क्या सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचता है? इन सवालों के जवाब ही पंचायतों के कार्यकाल की वास्तविक उपलब्धि तय करेंगे।

राजस्थान में चल रहे पंचायत चुनाव ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मतदाताओं के सामने अपने प्रतिनिधियों को चुनने के साथ-साथ गांव के विकास की दिशा तय करने की जिम्मेदारी भी है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को समझना होगा कि जनादेश अधिकार के साथ जवाबदेही भी देता है। सरकार को पंचायतों को पर्याप्त संसाधन और अधिकार देने होंगे तथा नागरिकों को उनके कामकाज पर नजर रखनी होगी।

लोकतंत्र की असली परीक्षा चुनाव जीतने में नहीं, बल्कि जनता के जीवन को बेहतर बनाने में है। पंचायत चुनावों की सफलता भी तभी मानी जाएगी, जब गांवों में विकास के वादे धरातल पर उतरें और आम ग्रामीण को अपने जीवन में उसका वास्तविक लाभ दिखाई दे।

–**अतिथि सम्पादक,**
राम शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार


प्रोफेसर (डॉ.) पी. सी. कंठालिया

राजस्थान ने कृषि शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसी क्रांतिकारी खोज की है, जिसके सामने दुनिया के बड़े-बड़े शिक्षा विशेषज्ञ भी नतमस्तक हो जाएंगे। अब कृषि वैज्ञानिक बनने के लिए न शिक्षक चाहिए, न प्रयोगशाला, न खेत में प्रयोग करने की जरूरत और न ही मिट्टी की पहचान का व्यावहारिक ज्ञान। जब बिना पढ़ाए डिग्री दी जा सकती है, तो पढ़ाने पर पैसा खर्च करने की जरूरत ही क्या है? इसी महान विचार को राजस्थान का नया कृषि शिक्षा मॉडल कहा जा सकता है-‘बिना पढ़े वैज्ञानिक बनो योजना’। उपलब्ध आँकड़ों

के अनुसार, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के स्वीकृत 38 पदों में एक भी पद भरा हुआ नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर के 1०0 पदों में से 92 और असिस्टेंट प्रोफेसर के 297 पदों में से 214 पद रिक्त हैं। अर्थात् शिक्षकों के लगभग 80 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। अशैक्षणिक कर्मचारियों के करीब 7० प्रतिशत पद भी रिक्त बताए जाते हैं। इसे प्रशासनिक विफलता कहना उचित नहीं होगा; आखिर यह सरकारी खजाने की बचत का अभिनव प्रयोग भी तो हो सकता है। वेतन पर खर्च नहीं होगा, तो बची हुई राशि से नई इमारतें बनेंगी, उद्घाटन समारोह होंगे और अखबारों में उपलब्धियों के विज्ञापन छपेंगे। शिक्षा की गुणवत्ता जैसे छोटें-मोटे प्रश्नों पर ध्यान देने से विकास की गति बाधित भी तो हो सकती है। शस्य विज्ञान विभाग इसका शानदार उदाहरण है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यहाँ 19 स्वीकृत शिक्षकीय पदों केविरुद्ध केवल एक प्रोफेसर कार्यरत हैं, जबकि लगभग 2० स्नातकोत्तर विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अब एक शिक्षक कितने विद्यार्थियों को पढ़ाए, कितने शोधार्थियों का मार्गदर्शन करे और

परीक्षा के दिनों में कुछ पन्ने याद कीजिए और कृषि स्नातक बन जाइए! खेत में बीज कब बोया जाता है, मिट्टी में किस पोषक तत्व की कमी है, खाद कितनी डालनी चाहिए और कीटों से फसल कैसे बचावी है–इन प्रश्नों का उत्तर बाद में भी खोजा जा सकता है। डिग्री पहले, ज्ञान बाद में! नौकरी मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। कृषि की डिग्री लेकर दूसरे व्यवसाय में चले जाइए। आखिर डिग्री तो डिग्री है; उसके पीछे वास्तविक ज्ञान की शर्त जोड़ना शिक्षा की स्वतंत्रता पर अनावश्यक प्रतिबंध ही माना जाएगा। छात्र परम सुखी है। चार साल तक हॉस्टल में रेश करो, रीत बनाओ, परीक्षा के पहले दो पेज रट लो, और लो – आप कृषि स्नातक बन गए! डिग्री है तो नौकरी की चिंता क्यों? और नौकरी न भी मिले तो क्या? पकोड़े तलना तो उठा ही होगा, वो भी तो कृषि आधारित उद्योग ही है। अध्यापक परम सुखी है। कॉलेज में एक ही है, तो क्लास लेने कौन जाएगा? वेतन हर सहीने खाते में आ रहा है, पढ़ाना नहीं पड़ रहा! इससे ज्यादा अच्छी नौकरी और क्या होगी? कुतूहल परम सुखी है। स्टाफ नहीं है तो फाइलें नहीं हैं, फाइलें नहीं हैं तो काम नहीं है। काम नहीं है तो

प्रोफेसर (डॉ.) पी. सी. कंठालिया,
पूर्व विभागाध्यक्ष (मृदा विज्ञान) एवं मुख्य वैज्ञानिक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर

अपशिष्ट से संपदा, तकनीक से समाधान: स्वच्छ व प्रदूषण मुक्त राजस्थान की ओर बढ़ते कदम

त्योहारों की खुशियों के साथ पर्यावरण संरक्षण का संकल्प, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक निगरानी प्रणालियों से प्रदूषण नियंत्रण को मिल रही नई दिशा


डॉ. अमृता कटारा

जयपुर। त्योहार भारतीय संस्कृति में उल्लास, परंपरा और सामूहिकता के प्रतीक हैं। दीपावली सहित विभिन्न पर्वों के दौरान बाजारों की रौनक, घरों की सजावट, रोशनी और उत्सव का वातावरण जनजीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। लेकिन उत्सवों की इस चमक के साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी भी जुड़ी है। त्योहारों के दौरान बढ़ने वाला ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक एवं पैकेजिंग सामग्री, फूल-मालाओं का कचरा, निर्माण एवं सजावटी सामग्री के अवशेष तथा पटाखों से उत्पन्न वायु प्रदूषण पर्यावरण के समक्ष कई चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। ऐसे में उत्सवों की सार्थकता केवल भव्य आयोजन तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह स्वच्छता, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता में भी दिखाई देनी चाहिए। वास्तविक उत्सव वही है, जिसकी खुशियां वर्तमान के साथ आने वाली पीढ़ियों के पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें।

आज अपशिष्ट प्रबंधन का दृष्टिकोण तेजी से बदल रहा है। जिस कचरे को कभी अनुपयोगी मानकर फेंक दिया जाता था, वही उचित पृथक्करण, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के माध्यम से उपयोगी संसाधन बन

सकता है। इसी प्रकार, आधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल निगरानी और वैज्ञानिक विश्लेषण प्रदूषण की पहचान, पूर्वानुमान तथा नियंत्रण के नए अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। राजस्थान के लिए यह बदलाव विशेष महत्व रखता है, जहां तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिक परिवर्धियों, परिवहन और मौसमी प्रतिस्धितियों के बीच पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना सतत विकास की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

तकनीक आधारित पर्यावरण प्रबंधन: समस्या की पहचान से समाधान तक पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में तकनीक का महत्व अब केवल प्रदूषण के आंकड़े एकत्र करने तक सीमित नहीं है। आधुनिक निगरानी प्रणालियां, डिजिटल प्लेटफॉर्म, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पूर्वानुमान आधारित विश्लेषण प्रदूषण नियंत्रण को अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी और समयबद्ध बनाने में सहायक हो सकते हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा वायु गुणवत्ता की सतत निगरानी, औद्योगिक उत्सर्जन एवं अपशिष्ट जल की ऑनलाइन निगरानी तथा वायु गुणवत्ता की पूर्व चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। मंडल की आधिकारिक वेबसाइट पर जयपुर, अलवर और भिवाड़ी के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की जानकारी उपलब्ध है। सतत परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली इस व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन केंद्रों के माध्यम से पीएम 2.5, पीएम 1० तथा अन्य प्रमुख वायु प्रदूषकों की निगरानी की जाती है। राजस्थान सरकार की वर्ष 2०26-27 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार, दिसंबर

2०25 तक राज्य में 46 सतत वास्तविक-समय परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र संचालित था। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत 57 केंद्र कार्यरत थे। ये व्यवस्थाएं वायु गुणवत्ता की स्थिति समझने, प्रदूषण के स्तर में होने वाले बदलावों का आकलन करने और आवश्यक नियंत्रणात्मक कदमों के लिए वैज्ञानिक आधार उपलब्ध कराती हैं। जयपुर, भिवाड़ी, अलवर जैसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में वायु गुणवत्ता की पूर्व चेतावनी प्रणाली का महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है। मौसम, हवा की गति और दिशा, तापमान तथा प्रदूषकों के स्तर से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करके संभावित रूप से खराब होती वायु गुणवत्ता के बारे में पहले से जानकारी प्राप्त करना संभव है। इससे संबंधित विभागों को धूल नियंत्रण, निर्माण गतिविधियों की निगरानी, सड़क सफाई, यातायात प्रबंधन और औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक कार्रवाई की तैयारी करने में सहायता मिल सकती है।

आधुनिक पर्यावरण प्रबंधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस प्रक्रिया को और प्रभावी बनाने की क्षमता रखती है। एआई आधारित विश्लेषण से विभिन्न निगरानी केंद्रों से प्राप्त आंकड़ों में पैटर्न की पहचान, प्रदूषण के संभावित स्रोतों का आकलन, ज़ोरखिम वाले क्षेत्रों की पहचान और नियंत्रण उपायों की प्राथमिकता तय करने में सहायता मिल सकती है। इसी प्रकार, सेंसर आधारित कचरा पात्र, डिजिटल अव्यव दैनिक्य और कचरा संग्रहण के आंकड़ों का विश्लेषण करके कचरा संग्रहण मार्गों को बेहतर बनाया जा सकता है तथा खुले में कचरा जमा होने की समस्या

पर समय रहते ध्यान दिया जा सकता है। राजस्थान में औद्योगिक विकास रोजगार, निवेश और आर्थिक प्रगति का महत्वपूर्ण आधार है। लेकिन औद्योगिक गतिविधियों के साथ वायु प्रदूषण, अपशिष्ट जल और ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन की जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। सतत विकास का उद्देश्य उद्योगों के विस्तार को पर्यावरणीय मार्गकों के अनुरूप बनाना है, ताकि आर्थिक गतिविधियों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के बीच संतुलन कायम रहे। राजस्थान राज्य प्रदूषण निरीक्षण मंडल की ऑनलाइन सतत उत्सर्जन एवं अपशिष्ट जल निगरानी प्रणाली के माध्यम से संबंधित औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषण संबंधी आंकड़ों की निगरानी की जाती है। राज्य सरकार की आर्थिक समीक्षा के अनुसार, दिसंबर 2०25 तक 666 औद्योगिक इकाइयों ने मंडल के ओसीसीएमएस पोर्टल को कॉन्फिगर किया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत निर्धारित श्रेणियों के अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों तथा अन्य चिन्हित प्रतिष्ठानों की निगरानी को महत्व दिया गया है। डिजिटल निगरानी से पर्यावरणीय मानकों की पालना का आकलन करने और संभावित विचलनों की पहचान करने में मदद मिलती है। हालांकि, निगरानी के साथ नियमित निरीक्षण, नमूनों का वैज्ञानिक परीक्षण और नियमों के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई भी उतनी ही आवश्यक है। विशेष रूप से वस्त्र प्रसंस्करण, रासायनिक उद्योगों और अन्य जल-गहन औद्योगिक गतिविधियों में अपशिष्ट जल का उपचार, उपचारित जल का पुनः उपयोग और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उचित संवाहन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। त्योहारों का मौसम

भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहा है सेंगोल

यह प्रतीक ऐतिहासिक रूप से, चोल साम्राज्य के दौरान सत्ता हस्तांतरण के समय नए राजा को सौंपने के लिए उपयोग किया जाता था। चोल शासक शैव थे। भगवान शिव के भक्ता। इसलिए उनके राजदंड पर अपने आग्रध के सबसे प्रिय योध और वाहन नंदी की अंकुति बनाई जाती थी। इसके पीछे पौराणिक कथाओं का वह आधार भी है जिसमें नंदी को भगवान शिव का वाहन भर नहीं माना गया है बल्कि वह धर्म और न्याय का रक्षक भी कहा गया है। नंदी की प्रथिमा राजा या शासक को निरंतर यह याद दिलाती है कि सत्ता का उपयोग निष्पक्षता, सत्य और न्याय के साथ प्रयोग की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। देश आजाद होने के अवसर पर लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक के रूप में 14 अगस्त 1947 की रात देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपा था। यह सेंगोल

नरेन्द्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया था। तमिल शब्द सेम्पई यानी नीतिपरायणता और कोल यानी छड़ी से मिलकर यह बना है। सनातन संस्कृति की मान्यता अनुसार ‘सेंगोल’शब्द संस्कृत के ‘संकु’यानी शंख से भी जुड़ा है। प्राचीनकाल में राजा जब गद्दी पर बैठता था तो अन्य परम्पराओं के साथ उसे सेंगोल यानी राजदंड भी सौंपा जाता था। इसलिए कि वह इससे जो भी अपराध करे, अन्याय करे, राज्य के अहित से जुड़ा कार्य करे या किसी प्रकार की अतिक्रान्त का वचन दे, उसे दंडित कर सके। इसे धारण कर राजा जब राजपुरोहित से आशीर्वाद लेता तो राजपुरोहित भी अपने दंड से राजा पर हल्का प्रहार करते हुए कहता था कि धर्म के प्रयोजन से सेंगोल का उपयोग हो। वह राजा से कहता कि यह धर्म से जुड़ा है

टेंशन नहीं है। सरकार ने बंगला दिया है, गाड़ी दी है, नौकर दिया है। तीन साल तक इस सुख को भोगो, फिर अगली यूनिवर्सिटी में चले जाओ। किसने कहा कि कुलपति को पढ़ाई देखनी होती है? कुलपति का काम तो कुलपति के भोगों, मित्रों के नली। एक रिपोर्ट में बताया गया कि 21 कैबिनेट मंत्रियों के 18-35 साल के बच्चों में से जिनके बारे में जानकारी मिली, उनमें से 15 के पास विदेशी डिग्री है या वे विदेश में पढ़ रहे हैं अब सवाल उठता है कि हमारे माननीय नेता अपने बच्चों को लाखों रुपये खर्च करके विदेश क्यों पढ़ने भेजते हैं? यह तो देशद्रोह है। अरे, बुला लो उन बच्चों को वापस आइए। ऐसे में एडमिशन दिलाओ। यहीं बिना पढ़े डिग्री मिलती है, बिना खेत गए वैज्ञानिक बनते हैं।अध्ययन है राजस्थान की यह कृषि शिक्षा क्रांति। दुनिया ने हरित क्रांति देखी थी, हमने “बिना शिक्षक क्रांति” देख ली।

प्रोफेसर (डॉ.) पी. सी. कंठालिया,
पूर्व विभागाध्यक्ष (मृदा विज्ञान) एवं मुख्य वैज्ञानिक, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर

पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को जन–आंदोलन में बदलने का अवसर भी है। दीपावली के दौरान घरों और बाजारों में सजावट, उपहारों की पैकेजिंग, मिठाइयों के डिब्बों, फूल–मालाओं और अन्य सामग्रियों से बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न होता है। वहीं, पटाखों से होने वाला धुआं और धूलकण वायु गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में उत्सवों के आयोजन से लेकर उनके बाद की सफाई तक पर्यावरण अनुकूल व्यवहार अपनाना आवश्यक है। इस दिशा में कुछ सरल लेकिन प्रभावी कदम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। घरों, बाजारों और सार्वजनिक आयोजनों में गीले एवं सूखे कचरे को अलग–अलग एकत्र करना, एकल–उपयोग प्लास्टिक से बचना, पुनः उपयोग योग्य सजावटी सामग्री अपनाना और खाद्य अपशिष्ट को वैज्ञानिक तरीके से संसाधित करना अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर बना सकता है। फूलों एवं जैविक अवशेषों से खाद तैयार की जा सकती है, जबकि कागज, धातु, कांच और उपयुक्त प्लास्टिक को अधिकृत संग्रहण एवं पुनर्चक्रण व्यवस्था तय कर चुकाया जा सकता है। त्योहारों के दौरान बाजारों, पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक आयोजनों में अतिरिक्त कचरा संठाहण व्यवस्था विकसित करना भी आवश्यक है। स्थानीय निकायों, व्यापारिक संघटनों, आवासीय समितियों और स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। साथ ही, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित निर्धारित मानकों और समय–सीमाओं की पालना सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

–**डॉ. अमृता कटारा,**
सहायक जनसंपर्क अधिकारी


पंडित अनिल शर्मा

ग्रह स्थिति-सूर्य-तुला, चन्द्रमा-मीन, मंगल-कर्क, बुध-तुला, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह
आज रविवोग दिन 12:5० तक है। रात्रि 8:32 से पुनः प्रारम्भ होगी। आज बुध वक्री दिन 12:42 पर होगा। आज पंचक है।
श्रेष्ठ चौघड़िया- शुभ 7:59 से 9:23 तक, चर 12:11 से 1:35 तक, लाभ-अमृत 1:35 से 4:25 तक।
राहुकाल- 9:०0 से 1०:30 तक, सूर्योदय 6:35, सूर्यास्त 5:47

राशिफल

शनिवार 24 अक्टूबर, 2026

आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शनिवार, विक्रम संवत-2०83, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 8:32 तक, व्याघ्राद योग रात्रि 9:०1 तक, तैत्तिल करण दिन 1:37 तक, चन्द्रमा आज मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति-सूर्य-तुला, चन्द्रमा-मीन, मंगल-कर्क, बुध-तुला, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह
आज रविवोग दिन 12:50 तक है। रात्रि 8:32 से पुनः प्रारम्भ होगी। आज बुध वक्री दिन 12:42 पर होगा। आज पंचक है।
श्रेष्ठ चौघड़िया- शुभ 7:59 से 9:23 तक, चर 12:11 से 1:35 तक, लाभ-अमृत 1:35 से 4:25 तक।
राहुकाल- 9:०0 से 1०:30 तक, सूर्योदय 6:35, सूर्यास्त 5:47

मेघ	वृष
 घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में मानसिक तनाव हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। अनर्गत कार्यों में समय खराब हो सकता है।	 आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा।

तुला	वृश्चिक
 परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। व्यावसायिक वातां सफल रहेगी।	 विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिवचर्या में सुधार होगा। अनहनी की आशंका से बचा हुआ मन का भय दूर होगा। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन	कर्क
 व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लेंगीं। व्यावसायिक कार्य शीघ्रतासुममार्ग से बनने लेंगीं। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक अशावासन प्राप्त होंगे। अवकं हूए कार्य बनने लेंगे। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु	मकर
 परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।	 घर-परिवार में चल रहे आपसी मतभेद दूर होने लेंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

सिंह	कुंभ
 शुभ कार्यों के लिए यात्रा संभव है। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक अशावासन प्राप्त होंगे। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित यात्रा संभव है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 व्यावसायिक कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण वातां हो सकती है। और महत्वपूर्ण योजना बन सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे।

मीन
 आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बनने लेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सहकता मिलेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।